औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद नवम्बर, 1991 के अन्त तक विदेशी फर्मों के साथ सहयोग करने के 380 से अधिक प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। इनमें से 100 से अधिक प्रस्तावों में विविध औद्योगिक क्षेत्रों जैसे औद्योगिक मशीनरी, विद्युत उपकरण, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, चिकित्सा उपकरण, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इत्यादि में लगभग 240 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परिकल्पना है। जिन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है उनमें से एक प्रस्ताव में प्रस्तावित भारतीय कंपनी को इक्विटी पूंजी में 51% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परिकल्पना है।

Implementation of recommendations on 4th Pay Commission in National Instruments Limited

3176. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1471 given in the Rajya Sabha on the 12th September, 1991 and state:

(a) whether Government have since received a memorandum dated 23rd October, 1991 from National Instruments Employees Union, Calcutta on the issue of implementation of recommendations of 4th Central Pay Commission in respect of employees of National Instruments Limited; and

(b) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) By virtue of Hon'ble Supreme Court's directions, a High Power Pay Committee (HPPC) was appointed for revision of pay scales of employees of Public Sector Units following Central DA pattern and National Instruments Limited (NIL) is required to modify its pay structure in accordance with the recommendations of HPPC. In view of the above, the recommendations of HPPC are applicable to the employees other than those Central Government employees who are on foreign service terms to NIL and are covered by the 4th Pay Commission's recommendation.

भारतीय सीमेंट निगम के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

3177. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमेंट निगम के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक जांच की जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1990 में अनेक संसद सदस्यों ने उनके विरुद्ध बहुत से आरोप लगाए हैं ;

(ग) क्या सरकार उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है और यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या रहा है ; और

(घ) क्या सरकार संबंधित अधिकारी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) उद्योग मंत्रालय को सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इण्डिया के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई किसी जांच की जानकारी नहीं है।

(क) से (घ) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इण्डिया के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विरुद्ध 1990 में संसद सदस्यों तथा अन्यों से प्राप्त अनेक शिकायतों की विस्तार से जांच की गई थी पर आरोपों को आधारहीन पाया गया।

Sale of Public Sector Undertakings shares to Mutual Funds

@3178. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government pripose to initiate a privatisation programme next month by offering a first lot of 'packets' of shares of select public sector undertakings for sale to mutual funds;

(b) if so, whether the modalities of the offer of 'packets' have been worked

@Previously Unstarred Question 1801, transferred from the 10th December, 1991

out in consultation with mutual funds; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (c) No, Sir. No privatisation has been initiated. However, disinvestment in selected Public Sector Enterprises upto 20 per cent to Mutual Fund is being considered and packets work out in consultation with Mutual Funds are under process.

फ्लटेड कारखानों के आवंटियों के लिए स्वामित्व अधिकार

3179. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओखला में दिल्ली प्रशासन द्वारा बनाए गए फ्लेटेड कारखानों के आवंटियों के लिए स्वामित्व अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उनसे क्या कीमत वसूल किए जाने की प्रस्ताव है ;

(ग) यह लागत निर्धारित करने का आधार क्या है ; और

(घ) यह काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, ओखला स्थित फ्लेटेड कारखाने किराया-खरीद लागत के पूरे भुगतान के बाद आवंटियों को स्थायी पट्टे के आधार पर हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) वसूल की जाने वाली कीमत का हिसाब हर मामले में अलग से लगाया जाता है ।

(ग) काम्पलैक्स में दो आकार के फ्लैटेड कारखाने हैं । हर आकार के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा निकाली गयी लागत 31-12-86 को इस प्रकार थी :-

क्रम सं०	फ्लैट का आकार	31-12-86 को लागत
	वर्ग मी	रु०
1.	46.00	1,36,318.00
2.	44.69	1,32,436.00

31-12-91 को देय लागत 1-1-87 से 31-12-91 तक की अवधि के लिए 12.25% की दर से ब्याज जोड़कर निकाली गयी है और फिर 31-12-86 तक की अवधि के दौरान पहले ही से दिए गए किराए को समायोजित करने के बाद इसे पांच किस्तों में विभाजित किया गया है, फिर देय किस्तों को 12.25% की दर से पूंजी में बदला गया है । 1-1-1987 से दिए गए किराए को किराया-खरीद लागत की किश्त का एक हिस्सा माना गया है ।

(घ) पात्र एककों के संबंध में इस योजना के 31-12-91 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

लघु उद्योग सेवा संस्थान पर होने वाला व्यय

3180. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु उद्योग सेवा संस्थान पर कुल कितना वार्षिक व्यय किया जा रहा है ;

(ख) इन संस्थान में कुल कितने मूल्य के उपकरण और मशीनें हैं ; और

(ग) 1990-91 और अप्रेल, 1991 से अक्टूबर, 1991 के दौरान संस्थान में उपलब्ध संसाधनों से लाभान्वित उद्यमियों की संख्या क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) : (क) वर्ष 1990-91 में लघु उद्योग सेवा संस्थानों तथा उनकी शाखाओं एवं विस्तार केंद्रों पर कुल 1296.31 लाख रु० का व्यय हुआ था ।

(ख) इन संस्थानों की कार्यशालाओं के संयंत्र तथा मशीनों का कुल मूल्य लगभग 500 लाख रु० है ।

(ग) इन संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों से 1990-91 और अप्रेल, से